

**न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर**  
(निर्णय बर्डजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-10/2010/भीलवाड़ा (2010/00028)

1. कल्याण पुत्र किशोर, जाति धाकड़, नि0 भगुनगर, तह0 जहाजपुर जिला भीलवाड़ा ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. परमेश्वर पुत्र देवकिशन,
2. नृसिंग पुत्र देवकिशन,
3. दुर्गाशंकर पुत्र देवकिशन,  
नाबालिगान बबिलायत पिता देवकिशन धाकड़, नि0 फलासिया, तह0 जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जहाजपुर ।

**रेस्पोंडेंट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 24.12.2009 प्रकरण संख्या 84/2009**

**उपस्थित:-**

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री रमजान मोहम्मद, वकील रेस्पों संख्या 2 व 3.
3. रेस्पों संख्या 1 अनुपस्थित ।

**निर्णय**

**दिनांक:-5.10.2017**

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2009 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

- 1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत कल्याण ने अधी०न्याया० में तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 554 निर्णय दिनांक 10.8.2007 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांत एवं उसके भाईयों के संयुक्त खाते एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि खसरा नंबर 1/2 रकबा 1.12 बीघा व खसरा नंबर 1/11 रकबा 18 बीघा, खसरा नंबर 6/1 रकबा 19.10 बीघा, खसरा नंबर 156 रकबा 4.13 बीघा कित्ता 4 कुल रकबा 26.13 बीघा में से 1/4 हिस्सा ग्राम भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित है। अपील में पारिवारिक सजरा अंकित करते हुए कथन किया कि हजारी के कोई पुरुष संतान नहीं होने एवं अपीलांत छोटा भाई होने के कारण हजारी हमेशा अपीलांत के पास ही रहा व अपीलांत ने हजारी की जीवनभर सेवा पुत्रवत् की है। हजारी ने अपने जीवनकाल में अपने हक व कब्जे की समस्त आराजियात अपीलांत को सौंप दी थी, तब से ही हजारी के हक व हिस्से की समस्त आराजियात को अपीलांत निरन्तर काशत करता चला आ रहा है। स्व० हजारी ने अपीलांत को अपना उत्तराधिकारी मानते हुए समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने मौखिक वसीयत कर दी थी। हजारी के एकमात्र पुत्री अनोपी की मृत्यु करीब 10-11 वर्ष पहले हो चुकी है। दिनांक 13.3.2006 को हजारी की मृत्यु हो गई है। अपीलांत ने स्व० हजारी का अंतिम संस्कार क्रिया कर्म सम्पन्न किये एवं समाज के रीति-रिवाज के अनुसार पगड़ी भी अपीलांत ने बांधी थी। हजारी की मृत्यु के बाद उसके हक व कब्जे की आराजियात अपीलांत के नाम विरासत से दर्ज होना चाहिये थी लेकिन राजस्व अधिकारियों ने विस्तृत जांच किये बिना एवं अपीलांत को सुनवाई का मौका दिये बिना दिनांक 10.8.2007 को नामांतकरण संख्या 554 रेस्प० के नाम दर्ज कर दिया जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 554 अपास्त किया जावे परन्तु अधी०न्याया० ने निर्णय दिनांक 24.12.2009 द्वारा अपीलांत की अपील को अपास्त कर दिया। अधी०न्याया० के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
- 2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट्स के उपस्थित होने एवं अधी०न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट्स की बहस सुनी गई। xx
- 3- अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि मृतक हजारी की पुत्री अनोपी का स्वर्गवास हजारी के स्वर्गवास के 10-11 साल पूर्व हो गया था। हजारी द्वारा अनोपी का स्वर्गवास होने के बाद गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मुख अपने हिस्से की आराजी व अन्य चल-अचल सम्पत्ति की मौखिक वसीयत अपीलांत के नाम कर दी थी व मृतक हजारी की आजीवन सेवा-सुश्रूषा अपीलांत ने ही की थी तथा हजारी की मृत्यु के बाद हजारी के क्रियाक्रम

अपीलांट के द्वारा ही किये गये थे । अपीलांट मृतक हजारी का छोटा भाई होने से उसके समाज के रीति-रिवाज अनुसार पगड़ी अपीलांट के बांधी गई थी । अपीलांट हजारी के जीवनकाल से उसके हिस्से की आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है । मृतक हजारी की आराजियात के संबंध में नामांतकरण आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार को अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करना चाहिये था लेकिन अधी०न्याया० ने ऐसा न कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 8 में पुत्री के पुत्र व पुत्रियों को भी प्रथम श्रेणी के वारिस में माना गया है एवं इसके आधार पर हजारी के दोहिते के पक्ष में नामांतकरण को सही स्वीकार किया जाना मानकर निर्णय पारित करने में अपने अधिकारिता का दुरुपयोग किया है, क्योंकि तहसीलदार, जहाजपुर ने नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नहीं की एवं ना ही अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया है तथा ना ही विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई जांच ही की गई है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० ने अपीलांट द्वारा वसीयत प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर निर्णय पारित किया है किन्तु अधी०न्याया० में भी अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे वह अपना पक्ष साबित नहीं कर सके थे । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधी०न्याया० के निर्णय को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अतिरिक्त जिला क्लर्क, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2009 एवं नामांतकरण संख्या 554 दिनांक 10.8.2007 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावे । xx

- 4- विद्वान वकील रेस्पोंडेंटस संख्या 2 व 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित भूमि में हजारी पुत्र किशोर 1/3 हिस्से का खातेदार है । हजारी के पिता किशोर के तीन पुत्र कमशः मोती, हजारी एवं कल्याण हुए । मोती पुत्र किशोर फौत हो चुका है जिसके वारिसान बरजी, गोपी, मगना व देबी है । हजारी भी फौत हो चुका है जिसकी पुत्री अनोपी थी तथा अनोपी की भी मृत्यु हो चुकी है एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 अनोपी के पुत्र होकर मृतक हजारी के दोहिते हैं जो हिन्दू उत्तराधिकार अधि० की धारा 6 के अनुसार मृतक हजारी के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं । अनोपी की मृत्यु उपरांत तहसीलदार ने हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 6 के अनुसार रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 554 तस्दीक किया है जो विधिसम्मत है । अपीलांट मृतक हजारी का भाई है जो अपने आपको हजारी के गोद जाना बताता है किन्तु गोद जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं । विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण की कार्यवाही में गोद जैसे जटिल विषय का निस्तारण नहीं किया जा सकता है । दोनों अधी०न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 के सेक्शन 6

एवं 8 का विश्लेषण कर विधिसम्मत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किये हैं जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांत निरस्त की जावे।

- 5-** हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांत का अपील में मुख्य कथन यह है कि अपीलांत मृतक हजारी का भाई है तथा अपीलांत ने ही मृतक हजारी की उसके जीवनकाल में सेवा सुश्रूषा की थी जिससे हजारी ने अपने जीवनकाल में अपीलांत के पक्ष में समाज के समक्ष उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की मौखिक वसीयत कर दी थी जिसके आधार पर अपीलांत के पक्ष में मृतक हजारी की आराजियात का विरासत नामांतकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांत ने अधी० न्याया० के समक्ष एवं ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के दौरान उसके पक्ष में वसीयत किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसके विपरीत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्प० संख्या 1 लगायत 3 मृतक हजारी की पुत्री मृतक पुत्री अनोपी के पुत्र है तथा इस तथ्य को अपीलांत स्वयं ने भी अपने अपील मीमों में स्वीकार किया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 8 में वर्णित प्रथम श्रेणी के वारिसान की सूची के अनुसार “पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्री का पुत्र, पूर्वमृत पुत्री की पुत्री, पूर्वमृत पुत्री की विधवा, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा” को प्रथम श्रेणी के वारिसान माना गया है। चूंकि रेस्प० संख्या 1 से 3 खातेदार हजारी की पुत्री मृतक अनोपी के पुत्र होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 8 की सूची अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार, जहाजपुर ने मृतक हजारी की विरासत का नामांतकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 8 के तहत रेस्प० के पक्ष में विरासत का नामांतकरण तस्दीक किया है जो विधिसम्मत है। प्रकरण में अपीलांत का यह तर्क रहा है कि हजारी ने अपीलांत को विवादित आराजियात की वसीयत कर दी थी किन्तु अपने कथन के समर्थन में अपीलांत ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं एवं वैसे भी नामांतकरण की कार्यवाही में वसीयत की वैधता का परीक्षण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 554 दिनांक 10.8.2007 एवं विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2009 में हम कोई विधिक एवं तत्यात्मक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांत अपारस्त योग्य तथा अधी० न्याया० का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

**-:क्रियात्मक आदेश:-**

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 10/2010 (2010/00028) बउनवानी कल्याण बनाम परमेश्वर को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 84/2009 बउनवान कल्याण बनाम परमेश्वर एवं तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 554 दिनांक 10.8.2007 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,  
अजमेर

आदेश आज दिनांक 5.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,  
अजमेर



